**'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलना**

3784. श्री राम लाल राही : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत निकट भविष्य में निर्मित की जाने वाली कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने के लिये तात्कालिक कार्यवाही नहीं की गई तो देश को करोड़ों रूपये की हानि होगी और श्रमिक भी बेकार हो जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस हानि को रोकने के लिये कब तक प्रयास किये जायेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (बालेश्वर राम): (क) से (ग). काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत यह अनिवार्य शर्त है कि राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा इस कार्यक्रम के अधीन सृजित सभी परिसम्पत्तियां स्थायी स्वरूप की होनी चाहियें। जहां तक ग्रामीण सड़कों का सम्बन्ध है, उन्हें स्थायी बनाने के पहलू पर विशेष रूप से बल दिया गया है। सड़कों तथा अन्य निर्माण कार्यों को स्थायी बनाने के लिये अपेक्षित सामग्री की खरीद हेतु नकद अनुदान अब राज्यों केन्द्र शासित क्षेत्रों को दिए जा रहे हैं। चालू वर्ष के लिए राज्यों को इस प्रयोजन हेतु 70 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। राज्य सरकारों से कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले निर्मित की गई सड़कों को स्थायी बनाने के लिए भी अपने निजी स्रोतों से निधियां जुटाने की प्रत्याशा की गई है ।

**Commercial flats in Nehru Place, New Delhi**

3785. SHRI DHARAM DAS SHASHRI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) how and under what authority the various property dealers in Delhi have started booking of Commercial Flats in the two Tower plots in Nehru Place before their auction and for which it is understood they have collected huge amount in crores;

(b) whether Government will sell the commercial flats after building up on these two plots by taking the value of the land which it expects in the auction and start registration on the first-come-first-serve basis in a self finance scheme; and

(c) whether in view of reply to part (a) do the Government propose to either cancel such auctions or postpone, till the whole matter is re-examined and a decision is taken on the basis of the above suggestion?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) The Delhi Development Authority have reported that these bookings do not have their sanction/approval. They do not know the amount collected by the property dealers.

(b) No, Sir. As per policy commercial plots developed by the Delhi Development Authority are disposed of by auction. The two commercial tower plots in Nehru Place stand disposed of.

(c) The disposal of the plots was done according to the policy laid down by Government. As such, the question of cancellation of the auctions does not arise.